खण्ड-07 सत्र-05 / अंक-59

मंगलवार 27 फरवरी, 2024 / 08 फाल्गुन, 1945 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

सातवीं विधान सभा

पाँचवां सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-07 सत्र-05 में अंक 50 से अंक 70 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

राज कुमार

सचिव

RAJ KUMAR

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप-सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-5 मंगलवार, 27 फरवरी, 2024/08 फाल्गुन, 1945 (शक) अंक-59

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	निधन संबंधी उल्लेख	3-4
3.	ध्यानाकर्षण	5-10
4.	विशेष उल्लेख (नियम-280)	11-42
5.	सदन में अव्यवस्था	43

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-5 मंगलवार, 27 फरवरी, 2024/08 फाल्गुन, 1945 (शक) अंक-59

दिल्ली विधान सभा

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

1. श्री अजेश यादव
2. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी
3. श्रीमती ए. धनवंती चंदीला ए.
4. श्री अजय दत्त
5. श्री अब्दुल रहमान
6. सुश्री भावना गौड
7. श्री बी. एस. जून
8. श्री धर्मपाल लाकड़ा
9. श्री गिरीश सोनी
10. श्री हाजी युनूस
11. श्री जय भगवान
12. श्री जरनैल सिंह
13. श्री करतार सिंह तंवर
14. श्री कुलदीप कुमार
15. श्री महेंद्र गोयल
16. श्री मुकेश अहलावत
17. श्री ओमप्रकाश शर्मा
18. श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर
19. श्री प्रवीण कुमार
20. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस

21. श्री प्रकाश जारवाल
22. श्री राजेश गुप्ता
23. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
24. श्री रोहित कुमार
25. श्री शरद कुमार चौहान
26. श्री संजीव झा
27. श्री सोमदत्त
28. श्री शिवचरण गोयल
29. श्री सोमनाथ भारती
30. श्री सही राम
31. श्री एस. के. बग्गा
32. श्री सुरेंद्र कुमार
33. श्री विशेष रवि
34. श्री वीरेंद्र सिंह कादियान
35. श्री मदन लाल
36. श्री पवन शर्मा
37. श्री प्रलाद सिंह साहनी
38. श्री राजेष ऋषि

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-5 मंगलवार, 27 फरवरी, 2024/08 फाल्गुन, 1945 (शक) अंक-59

दिल्ली विधान सभा

सदन 11.37 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

निधन संबंधी उल्लेख

माननीय अध्यक्ष: सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। माननीय सदस्यगण आप सबको विदित है कि प्रसिद्ध गजल गायक श्री पंकज उधास का लंबी बीमारी के बाद कल सोमवार, दिनांक 26 फरवरी, 2024 को निधन हो गया। वे 72 वर्ष के थे। उनका जन्म गुजरात के जेतपुर में 17 मई, 1951 को हुआ था। उनका जीवन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अपनी बेहतरीन आवाज के लिए उनको कई पुरूस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 2006 में पद्मश्री, वर्ष 2012 में महाराष्ट्र गौरव अवार्ड और उससे पहले संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, इंडियन फिल्म्स एंड टेलीविजन अकादमी अवार्ड और के.एल. सहगल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। फिल्म 'नाम' के गीत चिट्ठी आई के लिए उनको बेस्ट प्लेबैक सिंगर कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। उनका गाया हुआ गीत आज भी लोगों

के कानों में गूंजता रहता है जिसने उनके नाम को अमर कर दिया। उनके निधन से संगीत जगत को अपूर्णीय क्षति पहुंची है। वे अपनी गीतों और गजलों के माध्यम से अपने प्रशंसकों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूं तथा ईश्वर से कामना करता हूं कि उनके परिजनों तथा समस्त देशवासियों को इस अपार कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अब दिवंगत आत्मा के सम्मान में दो मिनट का मौन धारण किया जाएगा।

(सदन द्वारादो मिनट का मौन धारण किया गया।)

माननीय अध्यक्षः ओम शांति, शांति, शांति। मुझे खेद है आज कुछ इलेक्ट्रिक्ल deficiency के कारण सदन की कार्यवाही आधा घंटा देर से शुरू हुई है। शायद अभी मीडिया के बंधुओं को भी डायरेक्ट बाहर जो हम रिकॉर्डिंग के लिए देते है वो नहीं दे पाएंगे, बीच में जैसे ही ठीक होगा, वो रिकॉर्डिंग दी जा सकेगी। एमएलऐज जो बोलेंगे वो रिकॉर्डिंग सिस्टम ठीक हो गया है। 280, श्री भूपेन्द्र सिंह जून जी।

श्री बी. एस. जूनः धन्यवाद सर। सर, इससे पहले कि मैं अपना इशू under Rule 280 रूल 280 रखूं एक बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं जो सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि सभी विधायकों से संबंधित है। एक सर ऐसा लेटर आया है जिसमें विधायकों को वर्चुअली चोर कहा गया है, गाली दी गई है, मैं वो सदन के पटल पर भी रखूंगा और मैं चार लाईन पढ़ना चाहता हूं, विधायक साथी

डिसाइड कर लें कि ये सही है या गलत है। सर, ये लेटर है 22 फरवरी, 2024 का और लिखने वाले है, एडिशनल कमिश्नर– इंजीनियरिंग और ये आशीष कुंद्रा, 2024 का, आशीष कुंद्रा– प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इरीगेशन, फ्लड कंट्रोल को गया है, इस लेटर में सर चार लाईन जो कंक्लूजन है वो पढ़ रहा हूं– 'The field functionaries of MCD, Public Representatives, Members of Deliberative Wing, RWAs etc. have been complaining that the works underdiscretionary fund of MLA sanctioned by UD Department of Govt. of NCT of Delhi are initiatedè carried out without any intimationè prior permission especially during odd hours or Govt. holidays when the office filed functionaries of MCD are closed. It means सर हम चोरी से सिर्फ रात को काम कराते हैं एमएलए फंड का या सिर्फ छुट्टी वाले दिन काम कराते हैं। सर, अगर कोई भी सड़क बनती है तो उसमें महीनों लगते हैं, ओवर नाइट कोई सड़क नहीं बनती तो इस लेटर की लैंग्वेज बिल्कुल contemptuous है, defamatory है। इस अधिकारी को बुलाया जाए और इसके खिलाफ, इस मेटर को जो है प्रिविलेज कमेटी में रेुर किया जाए। सर, विधायकों की.. सर, विधायकों की इज्जत रखना आपके हाथ में हैं, इस सदन के हाथ में है। अगर ऐसे ये विधायकों पर एलीगेशन लगाएंगे कि छुट्टी वाले दिन काम कराया जाता है, रात को कराया जाता है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आप इसका संज्ञान लें और इनीशिएट करें action को।

....व्यवधान....

श्री बी.एस.जून: मैं सर ये लेटर..

....व्यवधान....

श्री बी.एस.जून: सर, विधायकों के सम्मान की रक्षा कौन करेगा?

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: भई कानून के तहत एक सदस्य कोई प्रस्ताव रखिये।

....व्यवधान....

श्री जरनैल सिंह: स्पीकर साहब मैं प्रस्ताव रखता हूं कि ऐसे अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, इनको प्रिविलेज कमेटी के माध्यम से कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए। ये मेटर इमीडिएटली प्रिविलेज कमेटी को रफेर किया जाना चाहिए।

....व्यवधान....

श्री बी. एस. जून: सर, मैंने इस पर 55 पर एक नोटिस दिया था, वो सदन में आज क्यों नहीं आया, मुझे नहीं मालूम लेकिन सर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका आप संज्ञान लें और जो उचित कार्रवाई हो सकती है, उसको कीजिए प्लीज। ये सबके सम्मान की बात है।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: बोलिये मदन लाल जी, क्या कह रहे हैं।

श्री मदन लालः सर, मैं ये कह रहा था कि इस पर आपने मुझे मौका दिया, ये बहुत ही सीरियस एलीगेशन है और हमने ये देखा है कि जब-जब हमने कोई भी सड़क बनाने की कोशिश की है, residents की एक सजेशन होती है कि इसको आप रात के समय बनाएं जब सब लोग सो जाते हैं, लोग अपने दफ्तर से, अपने कामों से लौटकर अपने घर चले जाते हैं। ये सबसे उत्तम समय होता है कि रात के 11 बजे के बाद रोड बने और 6-7 बजे तक वो बनता रहे, जिससे सुबह जब लोग चलना शुरू करें तब तक वो सुख ले क्योंकि दिन के समय इतनी मूवमेंट होती है सड़कों पर, खासकर गलियों में, ऐसे टाइम पर रोड बनाना बिल्कुल feasible नहीं है। छुट्टी के दिन हमने ये देखा है कि ज्यादातर लोग अपने घर पर मौजूद होते हैं, चौकीदारी करते हैं और वो ये देखते हैं कि उस सड़क को बनने से कोई खराब न करें। तो ये एक ऐसा काम है जो ज्यादातर छुट्टी के दिन और रात के समय ही होता है। दूसरी बात जब कभी होता है, हमने अपने यहां महसूस किया है कि इलाके का जेई अपने स्टाफ के साथ वहां मौजूद रहता है और जिस तरह की ये derogatory भाषा इस्तेमाल हुई है उससे ऐसा लगता है कि वो ये कह रहे हैं कि ये चोर हैं इसीलिए रात को छुपकर काम करते हैं। सर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण..

माननीय अध्यक्षः किया क्या जाए, ये सुझाव दीजिए, अपना प्रस्ताव दीजिए।

श्री मदन लालः सर, सुझाव ये है कि ऐसे ऑफिसर को, प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाए इस मेटर को,

माननीय अध्यक्षः वो तो आ गया।

श्री मदन लालः और वहां उनसे पूछा जाए कि after all ऐसी हिम्मत क्यों हुई है और वो कौन सी आरडब्लूऐ हैं, वो कौन से लोग हैं जो ऐसी सजेशन उनको दे रहे हैं। ये बिल्कुल कोई सजेशन नहीं देता। ये मनगढ़ंत है, काम को रोकने की एक नई साजिश है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं ये मामला प्रिविलेज को जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः चलिए। हां, विशेष रवि जी, बस,

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः भई इसी पर चर्चा करवा लूंगा क्या। सभी की भावना एक है।

....व्यवधान....

श्री विशेष रविः सर, ये बात बोलना कि सड़क जो है रात को नहीं बननी चाहिए,

माननीय अध्यक्षः वो हो गया, सुझाव दीजिए क्या करना है।

श्री विशेष रविः सुझाव, सर, एक बात बोलकर सुझाव दे रहा हूं मैं। हर डिपार्टमेंट का एक quality कंट्रोल जो है यूनिट होता है और वो

जो है सड़क ऐसा नहीं है कि रात को अगर डाल दी है तो वो सुबह तक बन गई और वो फाइनल हो गई। हर डिपार्टमेंट का जो quality कंट्रोल यूनिट है वो आकर उसको जो है, उसकी क्वालिटी वगैरह चेक करता है उसके बाद जो है उसकी फाइनल जो है सैंक्शन वगैरह होती है। तो ये कहना जो है अपने आप में जो है बड़ा जो है ये अजीब सी बात है। दूसरा मैं इस समर्थन का कि प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाए मेटर, समर्थन करता हूं इसका।

माननीय अध्यक्षः बस आखिरी है।

श्री रोहित कुमारः एक सुझाव सर इसमें छोटा सा कि जिस अधिकारी के नाम पर ये चिट्ठी लिखी गई है, उस सीनियर अधिकारी से भी जवाब तलब किया जाना चाहिए कि अगर आपके किसी अधिकारी ने ये, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, आपने उस पर क्या कार्रवाई की, आपने क्या संज्ञान लिया, उनसे भी पूछा जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्षः जरनैल सिंह जी का ये प्रस्ताव कि प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाए,

सदन इससे सहमत है तो हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

प्रिविलेज कमेटी को प्रस्ताव भेजा जाता है।

माननीय अध्यक्षः श्री भूपेन्द्र सिंह जी, जल्दी।

माननीय शहरी विकास मंत्री (श्री सौरभ भारद्वाज): सर, मैं एक छोटी सी बात आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में एमसीडी द्वारा लगातार इस तरीके के उलजलूल चिट्ठियां भेजी जा रही हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट्स को और मोटे तौर as a UD, Minister मैं ये समझता हूं कि सिर्फ काम रोकने के लिए एमसीडी के अंदर कुछ लोग बदमाशाी कर रहे हैं। अब तक मुझे 10 साल हो गए विधायक बने हुए, कभी एमसीडी से इस तरीके की पत्राचार नहीं हो रहे थे। ये पत्राचार क्यों हो रहे हैं, इस मामले को प्रिविलेज कमेटी को दिया जाए और प्रिविलेज कमेटी को ये कहा जाए कि 15-20 दिन में रिपोर्ट दे। ऐसा नहीं है कि हम प्रिविलेज कमेटी में तो देते रहते हैं, रिपोर्ट कोई नहीं आती है तो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो उसके अंदर 15 दिन का टाइमबाउंड करें। आप रोज बुलाओ अधिकारियों को और उसके अंदर रिपोर्ट पेश करो। इसी सदन में ये बजट सेशन के अंदर वो रिपार्ट आनी चाहिए वर्ना हम कोई, आचार संहिता के बाद कोई न इसको सुलझायेंगे।

माननीय अध्यक्ष: प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन कौन हैं। एक सेकंड। राजकुमार जी, प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन कौन हैं। सोमनाथ जी, सोमनाथ जी कितने दिन में रिपोर्ट देंगे?

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: एक सेकेंड भई दो मिनट रुक जाइये। सोमनाथ जी कितने दिन में रिपोर्ट देंगे।

श्री सोमनाथ भारती: विदइन वन वीक।

माननीय अध्यक्ष: नहीं वन वीक टू लेट, 01 तारीख को सदन पटल पर रिपोर्ट आ जाए।

श्री सोमनाथ भारती: ठीक है।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, हां जून साहब चलिए।

श्री सौरभ भारद्वाज: अध्यक्ष जी, मैं एक छोटी और बात कह रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि प्रिविलेज कमेटी के जैसे अध्यक्ष हैं वो बिजी हैं तो कमेटीज के अंदर ये प्रावधान होता है अगर अध्यक्ष नहीं आया तो जो मेंबर आए हैं वो अपना एक अध्यक्ष चुन सकते हैं तो वो चलता रहे काम कमेटीज का।

माननीय अध्यक्ष: चलिए ठीक है, जून साहब।

विशेष उल्लेख (नियम-280)

श्री बी एस जून: धन्यवाद अध्यक्ष जी, सर मेरे यहां एक वार्ड है बिजवासन और बिजवासन एक बहुत बड़ा गांव भी है। ये गांव इसके बीचों बीच से नजफगढ़, कापसहेड़ा सड़क गुजरती है और एक जो रेवाड़ी रेलवे लाइन है वो भी इसके बीचों बीच गुजरती है। पांच-छह साल पहले यहां एक रेलवे ओवरब्रिज या फ्लाईओवर बनाया गया और डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से उस फ्लाईओवर को बिलकुल गांव के बीच में ड्रॉप कर दिया जहां मेन चौक था। उससे क्या हुआ सर परपज

था कि फाटक बंद हो जाए, ट्रैफिक जाम होता था, उससे बढ़कर ट्रैफिक जाम होना शुरु हो गया। सैकड़ों गाड़ियां वहां फंसी रहती हैं जिसकी वजह से पाल्यूशन हुआ लोगों की सेहत पर असर पड़ा। मैंने सर जब सत्येन्द्र जैन साहब पीडब्लूडी मिनिस्टर थे उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने इसको एग्जामिन कराया और पीडब्लूडी ने रिपोर्ट दी कि हां ये फ्लाईओवर एक्सटेंड होकर और गौलोकधाम टैंपल के आगे क्रॉस करके जाना चाहिए था ताकि पूरे गांव का इसमें बचाव हो जाए। सर पीडब्लूडी ने एस्टीमेट बनाया, प्रपोजल बनाया, एलजी साहब को भेजा एलजी साहब ने एक डिपार्टमेंट है डीडीए में यूटीपैक उसको भेज दिया। सर 4 साल हो गये आज तक उस फाइल का कोई पता नहीं। लोग suffer हो रहे हैं, डेली ट्रैफिक जाम रहता है, घंटों ट्रैफिक जाम रहता है। सर एक साइड में गांव है दूसरी साइड में गांव है इधर अगर किसी की डैथ हो जाए तो दूसरी तो साइड में क्रिमिनेशन ग्राउंड है डैड बॉडी को सड़क क्रॉस करने के लिए आधा घंटा लग जाता है। तो मेरी पीडब्लूडी मिनिस्टर बैठी हुई हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक एटलिस्ट इसमें एक रिमाइंडर भेजकर यूटीपैक डिपार्टमेंट से ये पूछा जाए कि भई तुमने अभी तक फाइल पर क्या किया ताकि इसका काम आगे बढ़ सके, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू टाइम देने के लिए।

माननीय अध्यक्षः सहीराम जी, अनुपस्थित, राजेन्द्र पाल गौतम जी।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः धन्यवाद अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अपनी विधानसभा के क्षेत्र सुंदर नगरी में कैप्टन जावेद अली मार्ग पर अवैध तरीके से पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम

करके वहां पुरानी गाड़ियां काटी जाती हैं और उसमें सैकड़ों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है और उसकी वजह से पूरे उस क्षेत्र में जाम लगा रहता है और ओ–पॉकेट सुंदर नगरी में भी गाड़ी काटी जा रही हैं वहां भी अंदर पूरा जाम लगा रहता है लोग आकर हमसे शिकायत करते हैं। वहीं उसके पास में डीडीए का एक बड़ा ग्राउंड है के–ब्लॉक के सामने सुंदर नगरी में उस ग्राउंड में लगातार अवैध कब्जे हो रहे हैं। कई बार मैं अवैध कब्जे हटवा चुका हूं। एक तो मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करता हूं कि उप–राज्यपाल महोदय डीडीए से उस जमीन को जिस पर बार–बार कब्जे हो रहे हैं उसको उन गाड़ी काटने वालों को अलॉट कर दें, लीज पर दे दें, वो लोग किराया देने को तैयार हैं। तो कम से कम वहां रोड खाली हो जाएंगे और रोड पर अवैध कब्जे बंद हो जाएंगे और उन लोगों का रोजगार भी नहीं जाएगा और वो सुगमता से सरकार को रेवेन्यू देकर डीडीए को वहां पुरानी गाड़ी काटने का, पुरानी गाड़ियों के निस्तारण का काम अपना जारी रख पाएंगे और उनका रोजगार भी बचा रहेगा। और इसके साथ–साथ नई सीमापुरी में रोड नंबर–70 पर सीमापुरी डिपो के पास पूरे रोड पर कूड़ा बिनने वाले लोग उस रोड को लगभग पूरी तरह से बाधित किये हुए हैं वहां कूड़ा बीनने का काम करते हैं। कई बार मैं वहां लगातार सीनियर आफिसर्स को लेकर विजिट कर चुका हूं यहां तक कि मेयर साहब को भी लेकर मैंने विजिट किया और वहीं सुरक्षा नर्सिंग होम और कब्रिस्तान रोड नई सीमापुरी वहां पर भी काफी चौड़े रोड हैं लेकिन वो पूरे के पूरे रोड पर ही कूड़ा बीनने का काम होता है। गाड़ी से निकलना तो दूर की बात है लोग पैदल नहीं निकल सकते। तो मैं निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि एमसीडी अपने

वहां उनके खाली जगह है वहां खाली जगह पर उनको कूड़ा निस्तारण के लिए कूड़ा बीनने के काम करने के लिए उनका लीज पर जमीन दे दे, वो उसका किराया देने को तैयार हैं। और जखीरा पुल के पास एमसीडी ने एक चिंतन नाम के एक एनजीओ को एक बहुत बड़ी जमीन दी हुई है जहां कूड़ा निस्तारण का काम होता है लेकिन मैंने वहां जाकर विजिट किया। वहां मशीनें हैं लेकिन मशीनें बंद है कूड़ा निस्तारण का काम मशीन से होने की बजाय एमसीडी की फ्री में दी हुई जमीन का टोटल मिसयूज हो रहा है। सरकारी अस्पतालों से पूरा का पूरा जो भी वेस्ट है चाहे वो सीरिंज हों या प्लास्टिक की या दूसरी चीजें हों वो उनको फ्री में दी जाती हैं लेकिन वहां उसका निस्तारण प्रॉपर करने की बजाय सारा उन कूड़ा उठाने वाले लोगों को ही वो करोड़ों रुपये में बेच देते हैं। यानी जो फायदा होना चाहिए एमसीडी को वो एमसीडी को फायदा नहीं हो रहा। उस जमीन को एटलिस्ट हमारे जो रैगपिकर्स हैं, जो हमारे यहां कूड़ा बीनने का काम करते हैं उस जगह को उनको दे देंतो कम से कम रोड खाली हो जाएंगे, रोड पर कोई कब्जा नहीं होगा और वो लोग तो उसका किराया भी देने को तैयार हैं। तो मैं आपके माध्यम से एमसीडी से निवेदन करता हूं, यहां से सदन से चला जाए कि इन रैगपिकर्स को वो जो जगह उनको जखीरा में वहां दी हुई है या तो वही वाली जगह दे दें चूंकि वो चिंतन एनजीओ तो टोटल मिसयूज कर रही है उसका, पूरा फायदा उठा रही है, करोड़ों में उस कूड़े को बेच रही है जबकि जमीन एमसीडी ने फ्री में दी हुई है। इससे तो बेहतर यह है कि जो वास्तव में कूड़ा बीनने का काम कर

रहे हैं, जो वास्तव में कूड़े का निस्तारण कर रहे हैं अगर उनको वो जमीन दे दी जाए मैं तो कहता हूं वो तो एमसीडी को किराया भी देने को तैयार हैं, तो उनका रोजगार भी बचेगा, रोड भी साफ हो जाएंगे और एमसीडी को भी इससे लाभ होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे मेरे क्षेत्र की समस्या उठाने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री संजीव झा जी।

श्री संजीव झाः बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपनी विधानसभा के जहांगीर पुरी एरिया है हमारा, उसकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षण चाहता हूं। बेसिकली हमारे यहां जहांगीर पुरी में एमसीडी फ्लैट के सामने कुछ सरकारी भूमि है जिसका खसरा नंबर है 1441, 42, 43, 48, 1463, 64, 65, 71 ऐसे करके टोटल 24 खसरे हैं। अब ये खसरा की जमीन कुछ डिफेंस के पास है कुछ डीडीए के पास है। मैं तीन साल पहले हमने प्रधानमंत्री जी को भी, रक्षा मंत्री जी को भी और गृहमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी थी वहां से फिर जवाब आया था। उसके बाद कुछ कार्यवाही हुई और कार्यवाही करके डिफेंस ने अपने छोटे से एक टुकड़े को बाउंड्री कर लिया। चूंकि वो जो एरिया है उस एरिया में बहुत सारे कबाड़ी वाले अपना कबाड़ रखता है और क्राइम बहुत होता है। आए दिन वहां पर मर्डर की घटना तमाम तरह की घटनाएं होती हैं। तो फिर डिफेंस ने बाउंड्री कर लिया था और बाकी जगह पर एसटीएफ के जरिये डीएम ने उसको साफ करवाया था। अब वो जो बाकी एरिया है उस बाकी

एरिया में फिर उसी तरह का कबाड़ा रखा जा रहा है। रोज उसको जलाते हैं, जलाने से दुर्गंध भी जहांगीरपुरी के एरिये में आ रहा है और क्राइम भी बढ़ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो डीडीए का लैंड अपनी आइडेंटिटीफाई करे की उसकी कौन सी लैंड है और डिफेंस की कितनी लैंड रह गई है उसकी डिमार्केशन हो जाए और डिमार्केशन से पहले डीएम, एसडीएम को निर्देशित करे ताकी एसटीएफ के जरिये फिर एरिया को साफ कर दिया जाए। मैंने ये भी निवेदन किया था चूंकि पूरे जहांगीरपुरी में कहीं कोई श्मशान की भूमि नहीं है तो मैं लगातार डीडीए को इस मार्फत हम पत्राचार कर रहे थे कि ये जो जमीन है ये जहांगीरपुरी के लिए श्मशान के लिए दे दी जाए ताकी श्मशान का निर्माण वहां हो जाए। तो मैं यही आज आपके संज्ञान में और आपके जरिये माननीय मंत्री जी को निवेदन कर रहा हूं कि डीएम को निर्देशित करें ताकि कम से कम पहले वो खाली करा लिया जाए फिर डीडीए उसको बाउंड्री कर ले, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री सुरेन्द्र कुमार जी।

श्री सुरेंद्र कुमारः माननीय अध्यक्ष जी, आपने 280 पर बोलने का आदेश किया आपका धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका ध्यान अपनी विधानसभा क्षेत्र गोकलपुर की तरफ मंडोली मुख्य मार्ग की हर्ष विहार की तरफ दिलाना चाहता हूं। ये जो मुख्य मार्ग है ये मंडोली गांव को भी जाता है, हर्ष विहार को भी जाता है, बैंक कालोनी को भी जाता है, मंडोली एक्सटेंशन को भी जाता है। करीब ढ़ाई लाख लोग इस

क्षेत्र में इधर से आना-जाना है। तो माननीय अध्यक्ष जी मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मैं कई बार वहां डीडीए के वाइस चेयरमैन से भी मिला, आदरणीय हमारे सोमनाथ भारती जी जो हमारे डीडीए के सदस्य हैं, वो कमिश्नर लैंड से भी दो बार इन्होंने उनसे मीटिंग करी उसके बाद एलजी से भी इस बारे में मिला की भई ये करीब डेढ़ सौ गज करीब जगह है ये हमें रास्ते में दे दो क्योंकि वो जमीन ग्रीन बैल्ट की डीडीए की है। यदि वो रास्ते में हमें मिल जाए क्योंकि इसमें वहां एक मुख्य द्वार जेल का भी है तो उधर आना-जाना लगा रहता है लेकिन सुबह और शाम के समय तो दो-दो घंटे वहां जाम लगा रहता है। कई बार कोई दुर्घटना भी हो जाती है तो वहां पेशेंट वहां दो-दो घंटे खड़े होने के लिए मजबूर हो जाता है। तो आपसे मेरा कहने का तात्पर्य माननीय अध्यक्ष जी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण को 60 मीटर लम्बा रास्ता बनाने के लिए आग्रह किया गया है। इस संबंध में दिल्ली के विकास प्राधिकरण को हमारे माननीय सदस्य सोमनाथ भारती के द्वारा भी मिलकर आग्रह किया गया है। डीडीए के आयुक्त, (भूमि, लैंड) से विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष से वर्तमान उपराज्यपाल महोदय से भी मीटिंग भूमि प्राधिकरण के लिए आग्रह किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी मैं इस सदन के माध्यम से आपसे आग्रह करता हूं कि आप सदन के माध्यम से दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमेन को आवश्यक निर्देश जारी करें जिससे कि डीडीए की जमीन उन क्षेत्र के लोगों को रास्ते के लिए मिल जाए जिससे कि वहां पर लगने वाले जाम से निजात मिले। आपसे मैं ये निवेदन करना

चाहता हूं कि डीडीए तो वैसे जमीन देता नहीं लेकिन जो छोटा सा एक रास्ता है, वो रास्ते को यदि वो दे-दे तो कम से कम वहां जो जाम इंडस्ट्रीयल एरिया के लोग भी वहां से निकल जाते हैं, शोर्ट रास्ते को देखते हुए। तो माननीय अध्यक्ष जी आप डीडीए को आदेश करेंगे और मैं सदन का भी इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस तरफ वो ध्यान देकर डीडीए के वाइस चेयरमेन को आदेश करें जिससे किइस समस्या से निजात मिल सके। आपने बोलने का आदेश किया उसके लिए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः प्रमिला टोकस।

श्रीमती प्रमिला टोकसः धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी मेरी आरकेपुरम विधानसभा में एक मोहल्ला क्लीनिक बनवाने के लिए नेहरू एकता कैंप, आर.के. पुरम सैक्टर-7 के बस्ती विकास केंद्र-2 को चुना गया था। सारी उसमें सर्वे हो गया, सब कुछ हो गया। स्वास्थ्य विभाग ने डूसिब से जिसकी एनओसी जून, 2023 में मांगी थी, इसमें आठ महीने से अधिक समय हो गया परन्तु डूसिब ने अभी तक एनओसी नहीं दी है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगी कि डूसिब से जल्द से जल्द इसकी मंजूरी दिलाई जाए ताकि यहां मोहल्ला क्लीनिक का काम शुरू हो सके और यहां पर काफी कैंप है, झूग्गी-झोपड़ियॉं हैं, नेहरू एकता कैंप, एकता विहार, इंद्रा मार्केट कैंप, जे पी कैंप, अम्बेडकर बस्ती, कुष्ठ रोगी कालोनी, मलाई मंदिर कैंप, सोनिया गांधी कैंप, कम से कम सात-आठ कैंप है अध्यक्ष जी और इसमें मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि डूसिब से जल्द से जल्द इसकी एनओसी दिलाई जाए

ताकि यहां पर मोहल्ला क्लीनिक शुरू किया जाए और वहां के लोगों को इससे राहत मिले। क्योंकि वहां पर बहुत ही, कैंप में हैं तो गरीब ही लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्तः धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने मुझे मेरे क्षेत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर में पिछले दो साल से नए मोहल्ला क्लीनिक खुलने पर काफी कार्य चल रहा था। दस नई साइटों को देखकर फाइनलाइज करके, अप्रूव करके कर दिया गया, आज से करीबन 6 महीने पहले और मंत्री साहब जो पहले हैल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने और सौरभ भारद्वाज जी ने भी एक मीटिंग की और उसमें डिपार्टमेंट के साथ तो उन्होंने आदेश भी दिए की भई ये मोहल्ला क्लीनिक खुलने चाहिए क्योंकि अंबेडकर नगर में भी मोहल्ला क्लीनिक की संख्या बहुत कम है और उसके बावजूद ये मोहल्ला क्लीनिक नहीं खुले जिसकी वजह से बहुत सारे क्षेत्र के लोग उनके अंदर ये रोष भी है कि भई आप मोहल्ला क्लीनिक और ज्यादा क्यों नहीं खोल रहे। अंबेडकर नगर, जेजे आर और झूग्गी-झोपड़ी बस्तियॉं भी बहुत सारी हैं उनको सुविधा मिलनी चाहिए और माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे सीएम साहब ने पूरी दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लीनिक खुलाने के लिए काफी सारे कार्य किए हैं। सौरभ भारद्वाज जी के साथ दो बार मीटिंग हुई इस विषय में और उन्होंने बहुत मजबूती से विभाग को भी कहा, लेकिन मुझे समझ

नहीं आ रहा कि स्वास्थ्य विभाग के लोग अंबेडकर नगर में मोहल्ला क्लीनिक क्यों नहीं खोलने चाहते जबकि उन्हें सारी साइटें मिल चुकी है और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप विभाग को आदेश दें कि जितने भी मोहल्ला क्लीनिक की site अप्रूव हो चुकी है उनको तुरंत प्रभाव से खोलना शुरू करें और अध्यक्ष जी इसके साथ ही मैं एक चीज और यहां पर कहना चाहूंगा कि अंबेडकर नगर में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अथक प्रयास से 600 बैड का होस्पिटल खुल गया है और इस 600 बैड के होस्पिटल के अंदर कुछ सुविधाएं अभी शुरू की हैं जिसमें जच्चा-बच्चा के लिए और डिलीवरी के लिए महिलाओं के बहुत अच्छी सुविधा शुरू की गई है। मैंने इस सदन में पहले भी रखा था, वहां भी, क्योंकि 600 बैड का होस्पिटल है तो बहुत थोड़ी सी ही अभी हम सुविधा दे पा रहे हैं और मेरे ख्याल से उसको और बढ़ाना चाहिए। आपके माध्यम से मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से ये कहना चाहूंगा उनसे पहले भी मेरी इस विषय में बात हुई थी उन्होंने कहा था कि उसको आगे बढ़ाएं। तो इस पूरे होस्पिटल को चलाए जाए जिससे कि आसपास पूरी साउथ दिल्ली के लोगों को इसकी सुविधा मिले और अम्बेडकर नगर के लोगों को ये सुविधा मिले। इसमें एक महत्वपूर्ण जो चीजें हम काफी समय से डिस्कस कर रहे हैं मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ भी डिस्कस की थी, उन्होंने विभाग को बुलाकर कहा था कि अंबेडकर नगर में जो।

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी इसमें केवल विषय.

श्री अजय दत्तः बस एक सैकंड।

माननीय अध्यक्षः नहीं मेरी बात सुन लीजिए एक बार। इसमें केवल मोहल्ला क्लीनिक का विषय है। होस्पिटल का विषय कहीं नहीं है आप जो बोल रहे हैं वो डिस्कस नहीं हो पाएगा। होस्पिटल के लिए एक लाइन भी आपने कहीं डाली नहीं है।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी वो पीछे पेपर में था शायद वो आया नहीं इसमें।

माननीय अध्यक्षः चलिए।

श्री अजय दत्तः कोई बात नहीं मैं फिर भी अपनी बात रख रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः अभी समय है दूसरा लगाइए। होस्पिटल के लिए दूसरा लगाइए 280

श्री अजय दत्तः एक सैकंड में खत्म कर रहा हूं। तो अध्यक्ष जी, अस्पताल के अंदर महिलाओं के लिए डिलीवरी की जो सुविधा कर दी गई है, लेकिन वहां पर भी ओटी नहीं है और ओ.टी. ना होने के कारण अगर कोई ऐसा केस जो सीरियस केस वहां आ जाता है, अगर कोई उसकी वजह से प्रोब्लम करिएट होती है तो उसको या तो सफदरजंग रैफर किया जाता है या किसी और होस्पिटल में । तो मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षः भई इसके लिए दुबारा अभी समय है, 280 कल के लिए लगा दीजिए।

श्री अजय दत्त: ठीक है अध्यक्ष जी बस मैं खत्म कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष: महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री अजय दत्त: आप विभाग को इतना आदेश कीजिए की वहां पर महिलाओं के लिए डिलीवरी के समय में ओ.टी. की सुविधा करें, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (नेता प्रतिपक्ष): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार का ध्यान उस वायदे की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें सरकार ने 2022 के बजट में दिल्ली वासियों से ये वायदा किया था कि उनकी सरकार अगले 5 सालों में 20 लाख लोगों को रोजगार देगी। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2022 में बजट को ही 'रोजगार बजट' का नाम दिया था। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली सरकार ने पूरे दिल्ली में दस मेले भी लगाए, उनपर करोड़ों रुपया खर्च हुआ और दिल्ली सरकार ने इसके प्रचार पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ, दिल्ली सरकार ने 2015, 2017, 2018 और 2019 में भी बड़े-बड़े मेले आयोजित किए। इन पर भी करोड़ो रुपया खर्च हुआ। दिल्ली के जो बड़े-बड़े स्टेडियमस हैं उनमें ये मेले आयोजित किए गए, सरकार की ओर से करोड़ों रुपया खर्च किया गया। मैंने जब दिल्ली सरकार से ये जानना चाहा और मुझे दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने लिखित जानकारी दी है कि उनके पास कोई ऐसा रिकोर्ड ही नहीं है कि पिछले दो सालों में कितने लोगों को रोजगार दिया गया है।

आदरणीय अध्यक्ष जी सरकार के वायदे के मुताबिक की 20 लाख लोगों को 5 साल में रोजगार दिया जाएगा, तो 2022–2023, 2023–2024 में कम से कम 8 लाख लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था और मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार से जानना चाहता हूं कि वो बताएं की पिछले दो सालों में इन्होंने मेलों के ऊपर कितना पैसा खर्चा किया, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितना पैसा प्रचार पर खर्च किया। ये सदन में ये जानकारी मैं आपके माध्यम से दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहता हूं, बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। श्री जयभगवान जी।

श्री जयभगवानः माननीय अध्यक्ष महोदय आपने मुझे 280 के तहत बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान बवाना विधान सभा के अलग–अलग क्षेत्रों में ले जाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय सबसे पहले बवाना जेजे कालोनी में हमने डूसिब से जमीन लेकर के और तीन मोहल्ला क्लीनिक करीब–करीब डेढ़ साल पहले पास कराए थे मैंने सर और डेढ़ साल होने के बाद पीडब्ल्यूडी ने 12.5.2023 को पांच मोहल्ला क्लीनिकों का एस्टीमेट बनाया करीब 24 लाख 59 हजार। अध्यक्ष महोदय फिर दुबारा से, फिर उसके एक साल के बाद फिर उन्होंने एक एस्टीमेट बनाया 7 मोहल्ला क्लीनिक का, 4 करोड़ का। अध्यक्ष महोदय, डेढ़ साल से एस्टीमेट ही बन रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा। वहां पर जब हमने डेढ़ साल पहले वहां पर आपको जमीन दे दी और एक मोहल्ला क्लीनिक जो पहले से

वहां पर डूसिब का जो कम्यूनिटी सेंटर था वो मैंने हैंडओवर कराया है हैल्थ डिपार्टमेंट को और वो बिल्कुल रेडी है उसके अंदर भी मोहल्ला क्लीनिक तैयार नहीं किया गया। तो अध्यक्ष महोदय मैं सदन के माध्यम से चाहता हूं कि बवाना, जे.जे. कॉलोनी के अंदर जो तीन मोहल्ला क्लीनिक सेंशन हुये हैं उनमें से एक जो रेडी है उसे जल्दी से जल्दी चालू किया जाये दूसरा अध्यक्ष महोदय, एक खेड़ा गढ़ी के अंदर पिछले तीन सालों से मोहल्ला क्लीनिक चालू है उसके लिये कम से कम 15 मीटिंग मैं कर चुका हूं और बार-बार मैं बोल चुका हूं लेकिन वो मोहल्ला क्लीनिक भी चालू नहीं किया जा रहा जबकि उसके अंदर सारा सामान वगैराह सब कुछ कम्प्लीट रखा है उसके अंदर मीटर नहीं लगा था, मीटर भी लग चुका है, अध्यक्ष महोदय तीन साल हो गये। तो मेरा निवेदन है उसको चालू किया जाये और एक शाहबाद डेयरी के अंदर मोहल्ला क्लीनिक बनकर तैयार है उसे भी चालू किया जाये। अध्यक्ष महोदय, एक मेरा पॉली क्लीनिक है सैक्टर-23 के अंदर जो की करीब एक से डेढ़ साल पहले माननीय मनीष सिसोदिया जी जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने सैंक्शन किया था और 12 करोड़ रुपये सैंक्शन किये थे उसमें उसकी मैंने बिल्डिंग प्लान वगैराह सारा कुछ बना लिया और डिपार्टमेंट को भेज दिया उसको डिपार्टमेंट को भेजा हैल्थ को और सर पता नहीं वो क्या-क्या क्वेरी लगा रहे पिछले डेढ़ दो सालों से वो काम हमारा चालू नहीं हो पा रहा। मैं बार-बार जाता हूं उनके साथ कई मैंने मीटिंग कर लीं वो रोक दिया है, अध्यक्ष महोदय एक तो वो चालू किया जाये एक दूसरी मेरी पॉली क्लीनिक है सैक्टर-26 उसकी हमने

बाउंडरी वॉल वगैराह करा दी है बाकी उसका एस्टिमेट भी हम लोगों ने वहां भेज दिया है उसको भी जल्दी से जल्दी चालू किया जाये। अध्यक्ष महोदय तीसरा मेरा एक फुटओवर ब्रीज है जो वो करीब-करीब एक साल पहले वो भी सैंक्शन हुआ था वो भी माननीय मनीष सिसोदिया जी ने सैंक्शन किया था लेकिन वो भी पता नहीं क्यों किस कारण से रूका हुआ है, बीच में उसका एस्टिमेट नहीं बना फिर एस्टिमेट बनाकर हमने भिजवाया उसको लेकिन अभी फिर पता नहीं क्यों किस कारण से रोक दिया गया। तो अध्यक्ष महोदय ये मेरे जो तीन काम हैं इन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये क्योंकि ये सैंक्शन्ड है और जल्दी से जल्दी हो जायेंगे तो इनको जल्दी से जल्दी कराने की कृपा करें। मैं माननीय जो हमारी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि जो FOB है हमारी उस पर विशेष ध्यान दिया जाये, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ताः धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने 280 के तहत मुझे प्रश्न उठाने का मौका दिया और मैं आपसे ये वचन देता हूं कि मैं 280 के तहत अपने सिर्फ विधानसभा की बात करूंगा, कोई ऐसी राजनैतिक बात नहीं करूंगा कि औरों का समय खराब हो। अध्यक्ष जी, मैंने कल भी एक बात रखी थी कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी और उनकी कैबिनेट सारे विधायक मिलकर कोशिश करते हैं कि पंक्ति में खड़े हुये अंतिम व्यक्ति तक वो लाभ पहुंच सके क्योंकि वो वोट इसीलिये देता है बड़ी उम्मीद के साथ में कि जब मैं सरकार बना रहा हूं या बदल रहा हूं तो वो सरकार मेरे लिये कुछ करेगी। लेकिन

उनके इतने भरसक प्रयास के बाद में किस तरीके से लोगों को परेशान किया जाता है उसकी एक बानगी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कल मैंने labour card की बात करी। आज मैं आपको पेंशन के बारे में बात करता हूं कि जो दिल्ली सरकार विधवा पेंशन देती है इसके अलावा जो विधवा की बेटी की शादी में जो सहायता देती है 30 हज़ार रुपये की और 'लाड़ली योजना' इन सबके लिये पैसे देती है और उन सबको हमने काफी बढ़ाया भी है और आगे बढ़ाने का प्रपोज़ल भी एल.जी. साहब के पास है लेकिन फिलहाल जो है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जो पेंशन कार्यालय था वो मेरे ऑफिस से मेरी विधानसभा से तकरीबन तीन-चार किलोमीटर दूर था, गुलाबी बाग के अंदर, वजीरपुर के लोग वहां जाते थे तो क्योंकि ज्यादातर जो लोग इस योजना का फायदा लेने की कोशिश करते हैं वो महिलायें ही होती हैं क्योंकि विधवा महिला है अपनी बेटी की शादी के लिये पैसे मांग रही है तो ओबवियस्ली वो महिला होगी, बुजुर्ग होती हैं, ज्यादातर कम पढ़ी-लिखी होती हैं और गरीब होती हैं। वहां से बैटरी रिक्शा करके चली जाती थीं, किसी तरह अपना काम करा लेतीं थीं, हम मदद कर देते थे। अब इन्होंने उस कार्यालय को 15 किलोमीटर दूर करवा दिया है। मंगोलपुरी विधानसभा में भेज दिया है। कोई सीधी बस मेरी विधानसभा से वहां जाती नहीं, बैटरी रिक्शा वहां जा नही सकता, गाड़ी उनके पास है नहीं, टूव्हिलर उनके पास में है नहीं। अब 400-500 रुपये एक चक्कर के लगने लगे उनके, साथ में जो कागज़ हम गुलाबी बाग में देते थे और उनकी पेंशन लग जाती थी, 'लाड़ली योजना' का फायदा मिल जाता था

बेटी की शादी में पैसे मिल जाते थे, उसको पांच-पांच बार उन्हीं कागज़ों को वो बार-बार कैंसिल कर देते हैं, बार-बार कहते हैं ठीक नहीं है, बार-बार कहते हैं इन्हें बदलकर लाओ। छोटी सी फोटो के ऊपर लाइन आ गई जैसे आपने चंडीगढ़ का चुनाव देखा था ना लकीर आ गई इसको दुरूस्त कर दो, ऐसे तंग करते हैं। अब क्या हम उसके लिये सूप्रीम कोर्ट जायें? वो विधवा कहां से क्या करेगी बेचारी, कहां शिकायत करेगी? तो ये बहुत जबरदस्त परेशानी वजीरपुर विधानसभा को हो रही है। मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करता हूं, वैसे तो सर मैं बार-बार आपसे एक बात कहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहां पर सिर्फ गाल बजाने के लिये आया हुआ हूं। एक भी अधिकारी वहां नहीं है, एक सिंगल अधिकारी वहां पर नहीं बैठा हुआ। हां तो मैं तो ये चाहता हूं कि इसमें जोकि बिधूड़ी जी ने कहा था वो हमारा साथ देंगे सर एक privilege motion आपकी तरफ से जाना चाहिये कि अधिकारी यदि नहीं आ रहे तो इनको प्रिविलेज में हम बुला लें, आप दिल्ली की जनता का साथ दीजिये और मेरे को लगता है कि आप हमारे बड़े हैं, समझदार हैं, आपको हमसे ज्यादा तजुर्बा है, मुझे लगता है आप ये मोशन आप अपनी तरफ से लेकर आयें तो मैं आपका बहुत आभारी होऊँगा ये मेरी प्रार्थना है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री प्रवीण कुमार जी, अनुपस्थित, भावना गौड़ जी।

सुश्री भावना गौड़ः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने आज मुझे 280 में बोलने का..

माननीय अध्यक्षः प्रवीण जी अपनी सीट पर जायें। ये, बैठिये भावना जी दो मिनट बैठिये। भई माननीय सदस्यगण ये ध्यान रखें कि अपनी सीट पर बैठें, बोलते वक्त तो बिल्कुल सुनिश्चित कर लें कि मुझे अपनी सीट पर ही होना है।

श्री प्रवीण कुमारः धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, आज जो मैं समस्या उठाने जा रहा हूं ये युवा साथियों की बहुत गंभीर समस्या है और कुछ दिन पहले जो दिल्ली सरकार द्वारा डीटीसी की बसों में जो बस मार्शल लगाये गये थे उन बस मार्शलों को उठाकर जो है।

माननीय अध्यक्षः नहीं ये प्रवीण जी ये विषय नहीं है आपका, विषय है सहकारी बैंक।

श्री प्रवीण कुमारः ये वाला लगाया था अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः बिल्कुल नहीं, सहकारी बैंक का है आपके हाथ का लिखा हुआ है।

श्री प्रवीण कुमारः अच्छा।

माननीय अध्यक्षः कॉपी नहीं है मैं दे देता हूं।

श्री प्रवीण कुमारः अच्छा एक बार दे दीजिये फिर।

माननीय अध्यक्षः कॉपी दीजिये उनको।

श्री प्रवीण कुमारः पढ़ ही देता हूं अध्यक्ष जी। दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में OTS, one time settlement के तहत कितने लोन

सैट्ल किये गये एवं उनसे संबंधित खातेदारों की कॉपी दिलवाई जाये एवं क्या जिन लोगों के लोन OTS में सैट्ल किये गये हैं उनका केस आरसीएस कोर्ट में लम्बित है उनसे संबंधित फाइल की कॉपी दिलाने की कृपा करें। दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक के वर्तमान में चल रहे सभी अदालतों के केस की वर्तमान स्थिति की जानकारी दें एवं सभी फाइलों की कॉपी दी जाये। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में बहुत बड़ा एक इश्यू चल रहा है जिसमें One Time Settlement scheme के तहत कई सारे लोगों के जो है जो लोन है वो माफ कर दिये गये लेकिन आज तक जो है उनकी डिटेल नहीं दी गई कि किन लोगों के जो है वो ऋण माफ़ हुये और एक बहुत बड़ा स्कैम जो है वो दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में चल रहा है और मैं सदन पटल पर कई बार जो है इसके प्रश्न भी उठा चुका हूं, कई बार जो है इस मुद्दे को जो है वो प्रश्न के माध्यम से भी क्वेश्चन ऑवर में उठा चुका हूं लेकिन आज तक जो है उसका ना कोई जवाब आया और जवाब भी आता है तो गुमराह करने वाला जवाब आता है अध्यक्ष महोदय। तो अध्यक्ष महोदय मैं चाहता हूं कि ये जो डिटेल मांगी गई है मैंने ये सारी डिटेल जो है वो प्रोवाइड करी जाये आपके माध्यम से, बहुत-बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः भावना जी।

सुश्री भावना गौड़ः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने 280 में मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय मेरी अपनी विधानसभा पालम मैं डेवल्पमेंट के बहुत सारे काम चल रहे हैं, कहीं डीएसआईडीसी विभाग

द्वारा नाले और रोड़ बनाये जा रहे हैं तो कहीं एमसीडी द्वारा रोड़ों का निर्माण किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में आईजीएल द्वारा गैस की पाइपलाइन भी डाली जा रही है लेकिन अत्यंत तकलीफ की बात है कि इस विभाग के अधिकारी हमारी विधानसभा में अपनी मनमर्जी के अनुसार कार्य कर रहे हैं। ये बिना जानकारी दिये कहीं भी अपनी मर्जी से खुदाई का काम करते हैं बिना इस बात की चिंता किये कि जिस रोड़ पर खुदाई कर रहे हैं वह रोड़ कितने दिन पहले बना था। अध्यक्ष महोदय, आईजीएल अधिकारियों द्वारा जिस कार्यप्रणाली को अपनाया जा रहा है वह सबको बहुत निराश करने वाली है जनता भी इससे बहुत खिन्न है और दिल्ली सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्यों को भी सीधा–सीधा नुकसान पहुंच रहा है। अध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकारी काम एक निश्चित नियम के अर्न्तगत रह करके किये जाते हैं, कोई भी विभाग जब किसी दूसरे विभाग के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाली भूमि पर कार्य करता है तो वो उससे परमीशन के साथ–साथ आर.आर.कट. का पैसा भी उसे संबंधित विभाग को जमा करवाता है पर अध्यक्ष महोदय, आईजीएल के अधिकारी इन सब नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमर्जी से किसी भी सड़क को खोदकर कार्य कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पालम विधानसभा में ही नहीं अपितु यह विभाग पूरी दिल्ली में सीधा–सीधा नियमों की अनदेखी कर रहा है। आपसे निवेदन है आप स्वंय इस विषय पर संज्ञान लें, धन्यवाद।

....व्यवधान....

श्री राजेश ऋषिः ये इनके साथ में मेरी विधानसभा है दो-दो साल से ज्यादा हो गये लोगों के घरों में मीटर लगे हुये अभी तक कनैक्शन नहीं जोड़े गये, लाइनें नहीं डाली गईं। हमने सड़कें बना दीं, उनके नीचे से लाइन डाल रहे हैं और उसके बाद उन्होंने कई जगह सीवर की लाइनें तोड़ दीं, पानी की लाइनें तोड़ दीं, कुछ नहीं कर रहे जिसके कारण क्षेत्र में गंदा पानी भी आ रहा है। ये बिना परमीशन के काम करते हैं और किसी की नहीं सुनते हैं। मेरा आपसे जो भावना जी ने रखा है प्रश्न मैं भी चाहता हूं कि इस पर आप बुलाकर उनसे संज्ञान में लें कि क्या काम कर रहे हैं, क्यों नहीं ये काम कर रहे और सड़कें खुदी पड़ी हैं इनके कारण, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्रीमान मदन लाल जी।

श्री मदन लालः अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय मेरे यहां कोटला मुबारकपुर क्षेत्र में अमष्टत नगर एक कॉलोनी है जो purely residential colony है और उसमें प्रोपर्टी नम्बर-75-76 में Zepto नामक एक कम्पनी ने ऑन लाइन ट्रैडिंग का काम शुरू कर रखा है जिसमें घरेलू सामान की बिक्री वो ऑन लाइन करवाते हैं। यहां ऐसे सामान स्टोर किये जाते हैं जो ज्यादा inflammable हैं। अध्यक्ष महोदय, डिजास्टर दो तरह के हैं, एक नेचूरल है और एक मैन मेड हैं। नेचुरल में चाहे बाढ़ आती हो, भूकम्प आता हो, सुनामी आती हो पर कहीं-कहीं चूंकि नेचुरल पर हमारा कन्ट्रोल नहीं है तो हमारी ऐसी कोशिश रहती है कि मैन मेड डिजास्टर कभी ना हो। ऐसा ही एक बड़ा डिजास्टर हमें मुंडका में देखने को मिला, जो 13 मई, 2022 को हुआ। वहां एक बिल्डिंग में

चूंकि बिल्डिंग का फायर सेफ्टी आंकलन नहीं हुआ था, permissible property नहीं थी इसलिए वहां पर फायर की tragedy में 27 लोग मरे और 12 बुरी तरह घायल हुए। उसके बाद सरकार ने बहुत सारा कोशिश भी की, लीपापोती भी हुई और ऐसे लोगों का सरकार की ओर से भले ही कितने एक्शन हो जाते हों, ये और लोगों को ऐसे कृत्य करने से dissuade कभी नहीं करते। कभी भी ऐसा नहीं होता कि उनको देख कर लोग सीख लें और लोग तो छोड़ लोगों का अपना लालच है। ऐसी tragedies को देखने के बाद सरकारी एजेन्सीज जो इनके लिए जिम्मेवार हैं चाहे वो दिल्ली सरकार का डिजास्टर मैनेजमेंट हो, वो कब जागता है जब tragedy हो जाती है। tragedy होने से पहले कहीं tragedy हो सकती हो, उसका निवारण वो करने की कोशिश नहीं करते। tragedy होती है।. मैं सर उसी पर आ रहा हूं। tragedy होती है तो उसके बाद डिपार्टमेंट compensation देने का काम शुरू कर देता है। एमसीडी जिसकी जिम्मेवारी है कानून को लागू कराने की वो लोग केवल नोटिस देते हैं और उसके अलावा उनका कोई काम नहीं। सैटिंग हो जाती है और वो प्रॉपर्टी वो ही काम कर सकती है और ये ही दिल्ली सरकार के एक और डिपार्टमेंट फायर डिपार्टमेंट का है। फायर से एनओसी नहीं मिलती। पर चूंकि ऐसी प्रॉपर्टी में ऐसे बिजनेस चलते रहते हैं इसलिए फायर डिपार्टमेंट का काम भी चलता रहता है। दो साल पहले मैंने अपने क्षेत्र में डीसी जो दिल्ली सरकार के हैं उनके दफ्तर में इस प्रॉपर्टी की कम्पलेंट की कि इसमें outgress का कहीं भी प्रोग्राम नहीं है। अगर बिल्डिंग में एक बार घुस जाओ,

जहां inflammable सामान है घी है, तेल है, बोरी है, कपड़े हैं सब तरह का सामान है, प्लास्टिक है ऐसे में कभी भी आग लग कर ये बहुत बड़ी tragedy को आमंत्रित कर सकता है। दो साल पहले डीसी ने अपना पल्ला झाड़ दिया एक चिट्ठी लिखकर एमसीडी को कि एमसीडी इसको देखे क्योंकि हमारे पास infrastructure नहीं है और एमसीडी ने क्या किया। सर एमसीडी को जब मैंने कम्पलेंट की तो 20.04.2023 को एमसीडी को कम्पलेंट की, कमिशनर को और फायर के चीफ फायर ऑफिसर को करी। एक चिट्ठी दोबारा 01 मई, 2023 को चीफ फायर ऑफिसर को दी। 16.05.2023 को फिर डीसी, एमसीडी को दी चिट्ठी, मिला, उनसे बातचीत हुई और इतनी मशक्कत करने के बाद दो साल होने के बाद अंत में बहुत ज्यादा उनके दफ्तर में मैने आना जाना शुरू किया तो 16 जून, 2023 लगभग पौना साल हो गया, वहां के जेई ने अपने ऑफिसर्स को लिखा कि इस प्रॉपर्टी को ये building bye laws का वॉयलेशन है सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन्स का वॉयलेशन है, ये प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, commercial establishment नहीं चल सकता, ये बहुत बड़ा tragedy हो सकती है। तो ultimately 16.06.2023 के बाद 13 जुलाई, 2023 अब से लगभग साढ़े छः महीने पहले डीसी ने एक चिट्ठी लिखी occupier को कि आप इसको विदइन 48 ऑवर्स बंद कर दो नहीं तो ये प्रॉपर्टी सील कर दी जायेगी। आज साढ़े छः महीने गुजर गए हैं। 48 घंटे का नोटिस देने के बावजूद क्योंकि केवल ये करप्शन का मामला है। केवल ये जानबूझकर ऑंख मीचने मामला है। आज दिन तक उस प्रॉपर्टी पर कोई भी एक्शन नहीं लिया

गया है। ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं अभी पीछे तीन दिन पहले डीसी से मिला। वहां डीसी ने मुझे फिर कहा कि एक हफ्ते में हम आपको जवाब देंगे। आफ्टर आल ये क्या जवाब देंगे जब 48 घंटे का इन्होंने नोटिस दे रखा है 13 जुलाई को, तो अब तक वो प्रॉपर्टी या तो खाली हो गई होती या खाली नहीं हो रही है तो सील हो जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का सीधा-सीधा आदेश है और मैं तो कहता हूं सर मुंडका जैसी tragedy अगर हो गई वहां 23 लोग मरे थे सॉरी 27 लोग मरे 12 घायल हुए ये tragedy दिल्ली में लगभग रोकने की जरूरत है क्योंकि बहुत सारे establishment ऐसे ही बिना परमिशन, बिना फायर अप्रूवल के ये लगातार जारी हैं। लिहाजा मैं आपके माध्यम से ये आशा करता हूं कि ये establishment तुरन्त बंद होगा और अगर बंद नहीं होता तो सील होगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री महेन्द्र गोयल जी।

श्री महेंद्र गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी इस समय में दिल्ली के अंदर चारों तरफ त्राहि-त्राहि मची हुई है। अफसरशाही मची हुई है। मैं लारेंस रोड पर स्थिति एक पफैक्ट्री थी, उसके बारे में बात कर रहा हूं। चाइल्ड लेबर के हक में हम भी नहीं है कि कोई अपनी फैक्ट्रियों के अंदर कोई चाइल्ड लेबर रखे। लेकिन जहां पर बीस-बीस, तीस-तीस, चालीस-चालीस आदमी या पन्द्रह आदमी काम करते हैं वो ठेकेदारों के तहत काम करते हैं। हो सकता है कि उसमें उम्र भी किसी की कम होती होगी। उम्र कम है आप उसको लेंगे। फैक्ट्री वो सील कर दी। उसका प्रावधान एक

है कि उस बच्चे के लिए एक निश्चित राशि होती है जिसको वो जमा करवाया जाता है। फैक्ट्री वाले ने पूछकर अपने गलती मानते हुए ठेकेदार की गलती मानते हुए उन्होंने कहा भई कितने पैसे भरने हैं। उन्होंने जितने पैसे बोले उन्होंने उतने पैसे जमा करवा दिये। उसके बावजूद रिश्वतखोरी का बाजार इतना गर्म है, मेरी खुद की बातचीत करने के बावजूद भी मैने लेबर इन्सपेक्टर से भी बात की, मैने एसडीएम साहब से भी बात की। एसडीएम साहब ने बहुत को-ओपरेट करा इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन लेबर इन्सपेक्टर ने, कमिशनर ने, वहां पर बैठे अधिकारियों ने जिस प्रकार का रवैया अपनाया, यदि चाइल्ड लेबर को अंदर किया है एफआईआर तो उसी दिन होनी चाहिए। एफआईआर की कॉपी शनिवार तक भी वहां पर नहीं पहुंची। वो पैसे डीडी जमा करवा दिये जो मैं आपके पास के अंदर भी भेज देता हूं।जमा तक भी नहीं किया बोला अभी हमारे पास एफआईआर की कॉपी नहीं आई है। फैक्ट्री वाले का कसूर है क्या? तो इस प्रकार का मैं माननीय मंत्री जी को आप आदेश दें इस केस की इस प्रकार की जांच करें। कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति है तो आगे से इस प्रकार के व्यक्तियों को बढ़ावा ना मिले और मैं पूरी ईमानदारी के साथ में कह रहा हूं, कल जब रिश्वत के तौर पर उन अधिकारियों को पैसे दे दिये गए तो डी-सील हो गई। अदरवाईज वो फैक्ट्री डी-सील नहीं होती।

माननीय अध्यक्षः महेन्द्र जी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं। इसमें ना फैक्ट्री नम्बर है ना एरिया नम्बर हैं। कहां ये घटना हुई है। तो इसमें...

श्री महेन्द्र गोयलः मैंने घटना आपके पास भेज दी है।

माननीय अध्यक्षः नहीं घटना भेज दी।

श्री महेन्द्र गोयलः मैं आपके पास में मैं हार्ड कॉपी आपके पास में भेज देता हूं। जिस फैक्ट्री के बारे में।

माननीय अध्यक्षः इसमें 280 में जो आपने लिखा है, इस पर ना फैक्ट्री नम्बर है ना एरिया है।

श्री महेंद्र गोयलः हॉ नहीं है। उसके ऊपर मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं। क्योंकि ये तो मैने क्वेश्चन उठाने के लिए आपके पास में भेजा था और मैं अब ये सारी चीजें आपके पास में भेज देता हूं। ये सुनिश्चित भी किया जाए इस समय के अंदर चाहे कोई लाईसेंसिंग इन्सपेक्टर है या कोई भी किसी प्रकार का हाउस टैक्स का। ये इतनी गंडागर्दी चारों तरफ से हो रही है। दिल्ली के अंदर व्यापार करना मुश्किल हो गया है इस समय में और एक खास षड्यंत्र के तहत ये काम हो रहे है। तो पूरे के पूरे सदन को इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए एक आला अधिकारियों की आप और मंत्रियों की मिटिंग बुलाकर उस में सुनिश्चित करें कि इस प्रकार से एरिये के अंदर आदमियों को मत भेजें, जिस प्रकार से कि लोग त्राहि-त्राहि करें। धन्यवाद। जय हिंद। जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्षः अखिलेश त्रिपाठी जी, अनुपस्थित। विशेष रवि जी।

श्री विशेष रवि: धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, समाज कल्याण विभाग की तरफ से दिल्ली में एक योजना है। उसमें जो दलित समाज के जो महापुरूष हैं, संत महात्मा है उनकी जयंती पर एक अनुदान जो है वो क्षेत्र में लोगों को दिया जाता है एस.सी./एस.टी विभाग की तरफ से। लोग उसमें अप्लाई करते हैं और डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर लोगों की एप्लीकेशन की scrutiny करता है और उसके बाद जो है उनको जिन लोगों को सलैक्ट किया जाता है उनको अनुदान दिया जाता है। उस अनुदान के अंदर क्षेत्र में लोग जो है जयंती के मौके पर जैसे अभी 24 तारीख को श्री गुरू रविदास जी की जयंती थी तो उसके लिए भी जो है बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था। लोग जो है वेट करते रहे कि 24 से पहले जो है वो विभाग की तरफ से जो है इनकी ग्रांट आयेगी उनको जो है टैंट वाले का फोन आयेगा, जो वहां पर इलाके में उनको जयंती के मौके पर celebration करना है, उस जयंती को मनाना है, उसके लिए व्यवस्था करनी होगी। लेकिन लोग बाट देखते रह गए, लोग वेट करते रह गए लेकिन किसी भी टेंट वाले का या किसी एजेंसी वाले का लोगों के पास फोन नहीं आया। जब 24 तारीख निकल गई तो उसके बाद जब हमने पता करने की कोशिश करी तो ये पता लगा कि इस बार जो टेंडर हुआ उसके अंदर कोई आदमी नहीं आया टेंडर के अंदर और जब ये कारण पता करने की कोशिश की गई कि भई क्यों नहीं आया तो ये बताया गया कि पिछली बारी जो जयंती थी जैसे पिछली बारी भी दिक्कत आई थी पिछली जो जयंती थी वो महर्षि वाल्मीकि जी की थी तो उस जयंती के दौरान भी आखिर तक शायद

आखिरी दिन जो है लोगों के पास फोन आया कि भई आप जो है यहां कार्यक्रम कर लीजिए। और जब आखिर में फोन आया तो कुछ लोग कर पाए, कुछ लोग नहीं कर पाए। इस बार ना करने का कारण ये बताया गया कि टेंडर में कोई बंदा नहीं आया और उसका कारण ये रहा कि पिछले वाले जो टैंट वाला था जिसने काम किया उसकी पेमेंट नहीं हुई अभी तक। तो किसी की पेमेंट लास्ट कार्यक्रम की पेमेंट नहीं हुई इसलिए इस बार विभाग के टैंडर में जो है कोई भी bidder नहीं आया। तो मैं ये मुददा चाहता हूं उठाना आपके समक्ष की इसमें माननीय मंत्री जी और विभाग जो है संज्ञान ले कि ऐसा ना हो क्योंकि जितनी भी जयंती के कार्यक्रम होते हैं हमारे दलित समाज के जो महापुरूष हैं, संत महात्मा है लोगों की आस्थाएं उससे जुड़ी हुई हैं और हर साल जो है जब ये कार्यक्रम आते हैं तो लोग जो हैं वो बड़े उत्साह से जो हैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रतिक्षा करते हैं, तो इसका जो है देखा जाए। माननीय मंत्री जी जो हैं देखें कि आगे भविष्य में जो है इस तरह की घटना ना हो। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे 280 में अपनी बात रखने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, अभी भी आज भी माननीय अपोजीशन लीडर ने वो बातें उठाई जो माननीय केजरीवाल साहब ने कल अपने वक्तव्य में कहा था कि ये दो धारी करते हैं। उस तरफ हमें काम करने से रोकते हैं और फिर सदन में आके बोलते हैं कि आप काम नहीं कर रहे हो। आज भी

उन्होंने कहा है कि जो हमने एम्पलायमेंट की गारंटी दी थी कि आपने कितने इंपलायमेंट दे दिए, कितनी मेले लगा दिए लेकिन सर्विसिज डिपार्टमेंट इनके पास है ये बात साथ साथ में उनको बोलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, contractual workers को वादा किया गया था कि हम परमानेंट बनाएगें। कई बार सदन में बात उठी, माननीय केजरीवाल साहब ने खुद कही लेकिन सर्विसिज डिपार्टमेंट चूंकि अपने हाथ से छीन लिया गया इस करके इस पे काम नहीं हो पा रहा। आज मैं आप के माध्यम से वो 14 हजार contractual workers जो बीएसईएस के थ्रू employed हैं बीआरपीएल और बीवाईपीएल के जरिए उनकी पीड़ा आपके माध्यम से उठा रहा हूं। बहुत प्रयत्न किए गए कि बीएसईएस के जो 14 हजार इम्पलाईज हैं चूंकि उनका जो नेचर आफ जॉब है वो भी बड़ा क्रिटिकल है और हो क्या रहा है कि इस में सब का नुकसान है एक्सेप्ट जो मिडिलमेन है बीच में कंपनियां होती हैं दस बाय दस का कमरा होता है, वो बड़ी बड़ी कंपनियों से ठेकेदारी करती हैं, मोटा पैसा बीच में खाती हैं, जो इम्पलाइज है उसको कम पैसा मिलता है। बीएसईएस का नुकसान होता है, इम्पलाइज का नुकसान होता है, सरकार का नुकसान होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बात एलजी साहब तक पहुंचाना चाहता हूं कि केजरीवाल साहब के चाहने के लाख बावजूद ये contractual workers permanent नहीं हो पा रहे। ये बहुत चिंता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कई बार कहा कि वो जॉब जो परमान्टें नेचर के हैं अगर कोई व्यक्ति contractual employment में बहुत लंबे समय तक है तो उसका जॉब परमानेंट नेचर

का बन जाता है और इस कारण से ऐसे व्यक्तियों को अधिकार है और कंपनियों का दायित्व है कि ऐसे व्यक्तियों का जॉब परमानेंट में कनवर्ट कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इंटेंशन की बात है तो माननीय केजरीवाल साहब ने, आम आदमी पार्टी ने अपना इंटेंशन दिखा दिया चूंकि परमात्मा हमारे साथ है। एमसीडी में जब सरकार बनी तो अरविंद केजरीवाल जी ने contractual workers को परमानेंट करना शुरू कर दिया। कई तो हो गए तो जो भाजपा की मंशा थी कि केजरीवाल जी को गलत सिद्ध किया जाए, वो सफल नहीं हो पाए। उसी प्रकार से पंजाब में जब परमात्मा ने मौका दिया, पंजाब की जनता ने मौका दिया भगवंत मान साहब के नेतृत्व में सरकार चल रही है वहां पे भी कल भी 500 लोगों का उन्होंने कन्वर्जन किया, परमानेंट बनाया है। ये बहुत बड़ी बात है कि भाजपा के लाख चाहने के बावजूद केजरीवाल साहब की नीयत, आम आदमी पार्टी की नीयत एमसीडी में और पंजाब में हमने contractual को परमानेंट में कन्वर्ट किया। ये बात साफ साफ जाहिर हो गई।

माननीय अध्यक्षः कंक्ल्यूड करिए सोमनाथ जी। ये विषय से अलग जा रहा है।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, मैं वही उठा रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः नहीं विषय से अलग जा रहे हैं...

श्री सोमनाथ भारतीः चूंकि ये मेरी बार बार ये, चूंकि बार बार ये बार बार ही उठाते हैं इस बात को, मैं ये कह रहा हूं कि मैं उन

14 हजार जो इम्पलायज हैं बीएसईएस के उनको कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी ने जो आपको वायदा किया था कि कंवर्ट करेंगे contractual को परमानेंट में बनाएगें, ये वादा हम पूरा करके रहेंगे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। बीजेपी कितना भी चाह ले कि उन इम्पलाइज का सपना ना पूरा हो हमारे जरिए, वो सफल नहीं होंगे, उन 14 हजार लोगों को उनके परिवार को कहना चाहता हूं आम आदमी पार्टी आपको contractual से परमानेंट बनाने के लिए पहले कटिबद्ध थी, कटिबद्ध है कटिबद्ध रहेगी। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः नरेश बाल्यान जी, अनुपस्थित। पवन शर्मा जी अंतिम।

श्री पवन शर्माः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान आदर्श नगर विधानसभा की मजलिस पार्क कालोनी की तरफ दिलवाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न मैं पहले भी दो बार लगा चुका हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी पीडब्लयूडी की लैंड है जो मैट्रो को लीज पर दी हुई है और उसके बीच से नाला गुजर रहा है वो नाले में ब्लॉकेज है। उसका लेवल उंचा है तो मजलिस पार्क कालोनी में पानी भर जाता है, जरा सी भी अगर बारिश आती है तो लोगों के जो हैं बेड, साफे, फ्रिज पानी में डूब जाते हैं और बहुत नुकसान होता है और पिछले लगभग तीन साल से मैं प्रयास कर रहा हूं इसके लिए अधिकारियों को बुलाया गया, मौके पर दिखाया गया, एक नया नाला बनाने का भी प्रावधान एक्सईएन बिजेंद्र सिंह जी हैं रखा गया, उन्होंने भी बोला जी ठीक है एक नाला बना देते हैं हम, लेकिन उस पे कोई

कार्यवाई नहीं हुई है अध्यक्ष महोदय। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि कृपया मेरी समस्या का समाधान निकाला जाए क्योंकि जब भी मैं वहां से निकलता हूं तो लोग इकटठे हो जाते हैं और बार बार ये बोलते हैं जी बारिश आने वाली है और जो हैं हम डूब जाएंगे। कृपया कुछ समाधान कीजिए। मुझे 280 पर बोलने का मौका दिया बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

...व्यवधान...

(सत्ता पक्ष के सभी सदस्य बैनर लेकर वैल में आ गए और नारेबाजी करने लगे।)

माननीय अध्यक्षः कुलदीप जी, कुलदीप जी, वैल में मत आइए प्लीज। जरनैल जी वैल में मत आइए। मेरी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है वैल में ना आएं। वैल में ना आएं।

...व्यवधान...

(सत्ता पक्ष के सभी सदस्य बैनर लेकर वैल में आ गए और नारेबाजी करने लगे।)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य गण अपने स्थान पर बैठें। माननीय सदस्य गणों से प्रार्थना है अपने स्थान पर बैठें।

...व्यवधान...

(सत्ता पक्ष के सभी सदस्य बैनर लेकर वैल में आ गये और नारेबाजी करने लगे।)

माननीय अध्यक्षः सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

सदन पुनः 12.57 मिनट पर समवेत हुआ

माननीय अध्यक्ष (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

श्री जरनैल सिंहः स्पीकर साहब हमारा निवेदन है इस मसले को भी हल करें। स्पीकर साहब कोई फायदा ही नहीं हो रहा आने का।

...व्यवधान...

(सत्ता पक्ष के सभी सदस्य बैनर लेकर वैल में आ गये और नारेबाजी करने लगे।)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य गणों से प्रार्थना है सदन को शांति पूर्वक चलने दें। माननीय सदस्य गण, सदन की कार्यवाही बुधवार दिनांक 28 फरवरी, 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही बुधवार दिनांक 28 फरवरी, 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।